आर.पी.एस.सी. बताए भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक की कितनी शिकायतें मिली : हाईकोर्ट

- याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा कि परीक्षा की तीनों पारियों के पेपर लीक हुए थे और उसी दिन पूरे प्रदेश में 11 एफ.आई.आर. दर्ज हो गई थी। इसके बावजूद आर.पी.एस.सी. की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई
- याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि इस परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल नहीं किये गये थे, जो ऐसी परीक्षाओं में किया जाना आम बात है। इसके अलावा परीक्षा में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में बुधवार को याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को बहस जारी रखी जाएगी। वहीं अदालत ने आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग को यह बताने को कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयोग को पेपर लीक को लेकर कितनी शिकायतें मिली। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कहा कि परीक्षा की तीनों पारियों के पेपर लीक हुए थे और उसी दिन पूरे प्रदेश में 11 एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बावजूद आरपीएससी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान केवल तीन एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान कोई फोन के जैमर इस्तेमाल नहीं किये गये थे, जो ऐसी परीक्षाओं में किया जाना आम बात है। आर.पी.सिंह ने बताया कि परीक्षा में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि बड़ी विचित्र बात है कि आरपीएससी ने इस परीक्षा के लिये एक दिन में परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिये परंतु नाटकीय रुप से इसे तीन दिन कर दिया गया और फिर संभागीय जिलों के बाहर जाकर नये परीक्षा केंद्र बनाये जो कि नियम विरुद्ध था, बल्कि ऐसे ही एक परीक्षा केंद्र जो पाली में स्थित है में पेपर लीक होने और चीटिंग के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर भी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन सभी तथ्यों की वजह से आरपीएससी का पेपर लीक में भूमिका ओर भी संदिग्ध होती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया है जिनका आपराधिक बैकग्रांउड है या उनके माता-पिता अपराधी रहे हुए हैं या अपराधी संगठन से तालमेल रखते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जहां दागी अभ्यर्थियों को चिन्हित नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में भर्ती को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि याचिका कई महीनों बाद दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में से कुछ लिखित परीक्षा में फेल हुए, कुछ फिजिकल के बाद बाहर किए गए और कई साक्षात्कार में अंक नहीं ला पाए। यदि याचिकाकर्ता पास हो जाते तो फिर याचिका पेश नहीं की जाती। इसके अलावा एक याचिकाकर्ता तो एसओजी में ही कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान अदालती समय समाप्त होने के कारण अदालत ने प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को तय की है।

आर.पी.सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो सरकार के जबाव देने के बाद पुन: जबाव पेश करेंगे।

जयपुर-आभानेरी-भानगढ़ यात्रा के पोस्टर का विमोचन

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया।

जयपुर। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान के प्रतिनिधियो ने पर्यटन सचिव रवि जैन से मुलाकात कर जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी पोस्टर का विमोचन किया। जयपुर-आभानेरी-भानगढ़-जयपुर की यात्रा में पर्यटकों को 1 दिन के टूर में आभानेरी-चाँद बावड़ी, हर्षत माता मंदिर, आभानेरी विलेज के साथ लंच शाहपुरा आभानेरी रिसोर्ट में करवाया जायेगा। इसके साथ विश्व प्रसिद्द भानगढ़ किले का इतिहास भी बताया जायेगा। इस टूर में गाइड भी साथ रहेगा। इस टूर में प्रति व्यक्ति 2750 रुपए खर्च होगा।

पोस्टर विमोचन के दौरान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान अध्यक्ष तरुण कुमार बंसल, अधिराज सिंह शाहपुरा, सचिव, कुलदीप सिंह चंदेला, अध्यक्ष, असीम पारख, कोषाध्यक्ष, हुसैन खान, अध्यक्ष रणविजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कौशल राठौड़, उपस्थित थे। अधिराज सिंह ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जो पर्यटक खुद के व्हीकल से नहीं जा सकता या उसका बजट नहीं है कि वो पर्सनल कार वहन कर सके उनके लिए ये यात्रा है तथा उनके बजट में यह यात्रा सही है। जयपुर आने वाले पर्यटक एक दिन ज्यादा ठहराव करेंगे जिससे जयपुर में होटलों को इसका सीधा फयदा पहुंचेगा। इस यात्रा से घरेलु कलाकार, दुकानदार को भी फायदा होगा तथा ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण लोगो को रोजगार भी उपब्ध होगा। आने वाले दिनों में जयपुर-पुष्कर-जयपुर एवं जयपुर-सांभर-जयपुर के बीच में भी इस तरह कि यात्रा की शुरुआत करेगा। इस पोस्टर के विमोचन के दौरान पर्यटन सचिव ने धन्यवाद दिया। दिया कुमारी ने इसे सराहनीय कदम बताया जिससे राजस्थान के पर्यटन में इजाफा होगा तथा जयपुर के आसपास पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।

भाजपा सरकार में किसी भी विधायक-मंत्री का कोई फोन टैप नहीं हुआ : बेढ़म

- गृह राज्यमंत्री का कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार
- 'राज्य सरकार के एक साल के सुशासन को देखकर कांग्रेस घबराई'

जयपुर। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया, उन्होंने बता दिया कि उनका कोई फोन टैप नहीं हुआ और मैं गृह राज्यमंत्री के तौर पर कहता हूं कि हमारी सरकार में किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टैप नहीं हुए।

बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस के बयानवीर नेता सचिन पायलट को इस मुद्दे पर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। वे शायद भूल चुके हैं कि कांग्रेस के राज में खुद होटल में बंद रहे थे और इनको अपमानित भी किया गया था। इनके गुट के एक विधायक ने तो स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने आकर भी कहा था कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। उस समय अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कांग्रेस के नेता हमलावर थे लेकिन चुप रहे और बाद में गलबहियां भर रहे थे। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमियों से बचने के लिए सदन में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब बाधित करने का षडयंत्र किया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी। बेढ़म ने कांग्रेस के नेताओं को इस ओछी राजनीति को बंद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और इसी कारण उपचुनाव में आपका पत्ता भी साफ कर दिया। फिर भी कांग्रेस के लोग बयानबाजी करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता गुमराह नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राजस्थान के विकास को देखकर जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है।

बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा आमजन : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बैंक रहित परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरूआत की और इसका परिणाम यह हुआ कि जनवरी 2025 तक देशभर में 54.58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए। इनमें 55 प्रतिशत खाता धारक महिलाएं है। मोदी सरकार की ओर से विभिन्न वंचित वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी कई योजनाओं को शुरू किया।

डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने स्वीकारी अपनी गलती

- 'अनुशासन तोड़ा तो नोटिस मिला, मैंने नोटिस का जवाब दे दिया'

जयपुर। फोन टैपिंग मामले पर अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नोटिस मिलने के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से दिए नोटिस के जवाब में मीणा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री किरोड़ी मीणा ने अपने नोटिस और कांग्रेस के हंगामे पर जवाब दिया। नोटिस में क्या जवाब दिया, ये किरोड़ी ने नहीं बताया लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनसे अनुशासनहीनता हुई है, जिसकी वजह से पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया।

गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा ने अनुशासनहीनता का सोमवार को नोटिस जारी किया था। वहीं, बुधवार को मीणा ने नोटिस का जवाब संगठन को भेज दिया है। मीणा ने कहा कि मेरे से जो गलती हुई है, नोटिस में वह दर्शाई हुई है। गलती हुई थी, उसका जवाब दे दिया है। किरोड़ी कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी होती तो मैं मुस्कुराता नहीं हूं। अनुशासन तोड़ा है तो यह प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है। अगर वो जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो ही कार्रवाई के बारे में बता सकते हैं। कार्रवाई के बारे में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नहीं बता सकते।

बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा था। पार्टी ने किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को अनुशासनहीनता माना था। किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है, जिसका बुधवार को आखिरी दिन था।

दरअसल, किरोड़ी लाल के बयानों के कारण कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार को जमकर घेरा था। इसके बाद पार्टी हाईकमान एक्टिव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन राठौड़ से इस बारे में चर्चा की थी। इसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया था कि सार्वजनिक रूप से बयान देकर भाजपा नीत सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है।

राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को बनाया जा रहा है आसान : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को आसान बनाया जा रहा है इससे पर्यटन और फिल्म पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 व 9 मार्च को आईं आईं एफ ए 25 पुरस्कार समारोह आयोजित होना है, इससे राजस्थान पर्यटन को विश्व में भव्य पहचान मिलेगी। इससे राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग्स में भी बढ़ोतरी होगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिव पर्यटन विभाग रवि जैन एवं पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह की उपस्थिति में बुधवार को पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध आयोजित बैठक के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए उक्त जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इससे पूर्व बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को बिंदुवार आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान पर्यटन नीति तथा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में सरलता होनी चाहिए ताकि राजस्थान में पर्यटन को अधिकतम बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा राजस्थान पर्यटन का वैश्विक स्तर पर सशक्त ब्रांडिंग हो इस पर दोनों ही नीतियों में फोकस किया जाए।

दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन नीति के द्वारा सेगमेंटवाइज नवाचार किए जाए जिससे पर्यटन से जुड़ी इकइयां और स्टेकहोल्डर्स तथा अन्य सभी राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना अधिकतम योगदान दें सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में डिजिटल इनीशिटिव को भी शामिल किया जाए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आईं आईं एफ ए 25 पुरस्कार समारोह साकार रूप लेने जा रहा है। इसके सफल आयोजन की तैयारियां चल रही। इससे सम्बंधित कई तरह की शूटिंग भी राजस्थान की विभिन्न लोकेशन्स पर चल रही हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को इस दौरान लाँच किया जाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि फिल्म नीति सरल बनाया जाए ताकि राजस्थान में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो जिससे राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा मिले। उपमुख्यमंत्री ने कहा दोनों नीतियों से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही यहां के लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे।

सुधांशु महाराज 15-16 फरवरी को जयपुर प्रवास पर

सुधांशु महाराज

जयपुर । विश्व जागृति मिशन (विजामि) के संस्थापक और देश के जाने माने आध्यात्मिक संत आचार्य सुधांशु महाराज के पावन सानिध्य में गुलाबी नगर वासियों को दिव्य भक्ति सत्संग में धर्म और अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने का सुअवसर मिलेगा। विजामि प्रमुख आचार्य सुधांशु महाराज शनिवार और रविवार को अपने जयपुर प्रवास के दौरान विशेष सत्रों में श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन में सकारात्मकता, आनंद और उल्लास के साथ प्रगति के नए सोपान तय करने के गुर सिखाएंगे।

विश्व जागृति मिशन जयपुर मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे इस दिव्य भक्ति सत्संग के लिए आचार्य सुधांशु जी महाराज शनिवार को जयपुर पहुंचेंगे। प्रधान श्री मदन लाल अग्रवाल ने बताया कि आचार्य श्री सुधांशुजी महाराज शनिवार को गुलाबी नगरी पहुंचने के बाद आदर्श नगर में बीस दुकान स्थित सोमश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित जयपुर मंडल के आश्रम में श्रद्धालुओं और शिष्यों से मुखातिब होंगे और जयपुर मंडल द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का अवलोकन करेंगे।

जयपुर मंडल प्रधान ने बताया कि रविवार को जवाहर नगर के सैक्टर-4 में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षिशला ऑडिटोरियम में दिव्य भक्ति सत्संग के दो विशेष सत्रों का आयोजन होगा। पहला सत्र प्रात:: 10 से 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित होगा। इन सत्रों में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा, गुलाबी नगर वासियों को पहले आओ-पहले स्थान पाओ के आधार पर ऑडिटोरियम में प्रवेश दिया जाएगा। आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज इसी दिन दोपहर 12 बजे तक्षिशला ऑडिटोरियम में ही नए श्रद्धालुओं को दीक्षा देंगे।

'ईआरसीपी में 13 जिलों को मिलेगा पेयजल'

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने सदन में ईआरसीपी को लेकर सवाल पूछा जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने इस एमओयू की जानकारी प्राप्त हुई। घनश्याम तिवाड़ी ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में ईआरसीपी को लेकर एमओयू की जानकारी मांगी थी जिसके बाद मंत्रालय से प्राप्त लिखित जवाब में बताया गया कि राजस्थान को पेयजल के लिए 1744 एमसीएम, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीय कॉरिडोर को 205 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1360 एमसीएम पानी देने की बात कही गई है।

तिवाड़ी ने कहा है कि इस जवाब के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नए ईआरसीपी प्रोजेक्ट में राजस्थान को न केवल सिर्फ़ पीने का पानी मिलेगा बल्कि सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के इस समझौते को लेकर लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो गए हैं।

कानून का दुरुपयोग कर दायर जनहित याचिका खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग कर जेडीए की योजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश भगवान सहाय चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पूर्व में भी समान मुद्दे पर जेडीए के विकास को रोकने के लिए एक अन्य प्रार्थी के साथ याचिकाकर्ता बनकर पीआईएल दायर की थी। उस याचिका को अदालत ने 5000 रुपए हर्जाने सहित खारिज किया था। पीआईएल के नाम पर कानून के दुरुपयोग करने का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। यह याचिका एक तुच्छ प्रकृति की है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक लाख रुपए की हर्जाना राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए।

जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जेडीए की रोजदा फार्म हाउस योजना जालसू, फार्म हाउस एंड इको फ्रेंडली हाउसिंग स्कीम जयरामपुरा, रामपुरा डाबरी व अटलविहार आवासीय योजना, नारी का बास को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह स्कीम चारागाह जमीन पर विकसित की जा रही हैं। इसलिए इन योजनाओं की क्रियान्विति को रोका जाए। इसके जवाब में जेडीए का कहना था कि यह स्कीमें कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही विकसित की जा रही हैं। याचिकाकर्ता पहले भी फार्म हाउस योजना को जनहित याचिका के जरिए चुनौती दे चुका है।

कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता : कुमावत

- पशुपालन मंत्री ने तरल नत्रजन भंडारण के लिये 13 जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया

जयपुर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3- 3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।

वर्चुअल लोकार्पण के बाद कुमावत ने वीसी से जुड़े जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात की और साइलो की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जिलों के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों और पशुओं के हित के लिए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जिलों में पहुंचा दी गई हैं। अब राजस्थान को इस क्षेत्र में पहले नंबर पर लाना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है।

इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने जयपुर जिले के मैत्री कार्यकर्ताओं को ए आई किट का वितरण भी किया। उन्होंने मैत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में 218 लाख रुपये के नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिलों धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, बून्दी और कुचामनसिटी में 3 हजार लीटर की क्षमता वाले साइलो की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी।

इस अवसर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद थे।

राजस्थान में वर्ष 2025-26 में 4.40 लाख करोड़ रु. के ऋण वितरण का आंकलन किया नाबार्ड ने

- सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान : दक

जयपुर (कासं)। राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रु 4.40 लाख करोड़ के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया। इस मौके पर सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल, एसकेएनएयू, जोबनेर के कुलपति बलराज सिंह, राजफैड के प्रबंध निदेशक टीकम चंद बोहरा, और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच भी मौजूद थे।

सहकारिता मंत्री ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गई ऋण योजना और स्टेट फोकस पेपर 2025-26 की सराहना की। उन्होंने बैंकों संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों को नाबार्ड द्वारा स्टेट फोकस पेपर में किए गए अनुमानों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कंप्यूटरीकरण, नई

सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने नाबार्ड द्वारा बुधवार को आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया।

बहुउद्देश्यीय की स्थापना, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, सहकारिता में सहकार पर राष्ट्रव्यापी अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकां की मजबूती को शामिल किया है।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने राज्य फोकस पेपर 2025-26 के महत्व पर जोर दिया। राजपाल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण में नाबार्ड के प्रयासों का उल्लेख किया और मई 2025 तक 5000 पैक्स को "गो लाइव" करने के सरकार के लक्ष्य को साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य में भंडारण और खरीद सुविधाओं में सुधार के लिए सहकारी क्षेत्र में 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 150 गोदाम बनाये जा रहे है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच ने स्टेट फोकस पेपर के विषय में बताते हुए कहा कि कुल अनुमानित ऋण संभाव्यता में 47 प्रतशत कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए आंकलित किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि आवास, शिक्षा आदि के लिए 8 प्रतिश आकलित किया गया है। उन्होने बताया कि एसएफपी में आकलित ऋण संभाव्यता का उपयोग वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करने के लिए एक आधार दस्तावेज़ के रूप में किया जाएगा। डॉ. सिवाच ने आगे यह कहा कि कृषि आधारभूत सुविधाओं में निवेश में वृद्धि, कृषि उपज के समूहीकरण, मूल्य संवर्धन और किसानों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। सेमीनार के दौरान, राज्य में वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और कृषक उत्पादक संगठनों को भी सम्मानित किया गया।